Regularisation of Out-of-turn allotment of Petrol Pumps etc.

4104. DR. D. VENKATESHWAR RAO: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether an all-party meet has been convened on regularisation of out-of-turn allotment of petrol pumps, gas agencies etc.;

(b) if so, the outcome of the meeting; and

(c) if not, the steps proposed in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No such proposal is under consideration. Government has abolished the system of discretionary allotments.

Pilferage of diesel from Pipeline

4105. SHRI AMAR SINGH: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that more than one lakh litres of diesel gets pilfered every three months from the Kandla-Bhatinda pipeline in Gujarat region;

(b) whether similar pilferage has been noticed in other parts of the country and if so, the details thereof;

(c) how much loss Government has suffered till date; and

(d) what steps Government have taken to check it and with what results during the last one year?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR): (a) to (c) IOC have reported 16 incidents of oil pilferage since the commissioning of Kandla-Bhatinda Pipeline in December, 1995, out of which 10 are in the State of Gujarat and the remaining 6 are in the State of Rajasthan, resulting in total loss of diesel due to pilferage as 4017 KLs including 3625 KLs in Gujarat.

(d) The matter was taken up with State Governments of Gujarat & Rajasthan for taking appropriate action. FIRs have also been lodged in cases of pilferage. For ensuring safety of pipeline IOC has also intensified patrolling of pipeline including helicopter surveillance.

सरकारी समितियों को गैस की एजेंसियों का आवंटन

4106. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ सहकारी समितियों को गैस की एजेंसियां देने हेतु इंडियन आयल कार्पोरेशन तथा सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) क्या यह सच है कि 19 उपभोक्ता सहकारी समितियों को ऐजेंसियां दिये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, हां इंडियन आयल कार्पोरेशन ने बताया है कि उन्हें रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड को बरेली तथा लखनऊ मंडलों के अधीन 19 स्थानों पर एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें देने के लिए अनुरोध किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विद्यमान नीति के मुताबिक सहकारी समितियां सरकार द्वारा एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के सीधे आबंटन के लिए पात्र नहीं है। सरकार द्वारा डीलरशिपों/ डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का सीधा आवंटन नहीं किया जा रहा है। सहकारी समिति डीलर चयन बोर्डों के माध्यम से सामान्य चयन प्रकिया के अनुसार विज्ञापनों के प्रति डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आवंटन के लिए प्रत्येक श्रेणी के प्रति आवेदन कर सकती है।

Insufficient allotment of Kerosene to Kerala

4107. SHRI C.O. POULOSE: Will the Minister of PETROLEUM AND NAUTRAL GAS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the